उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 5 1-15 मार्च 2023 ₹ 20/-

ईरान और सऊदी अरब में समझौते से विश्व की राजनीति में नया मोड़

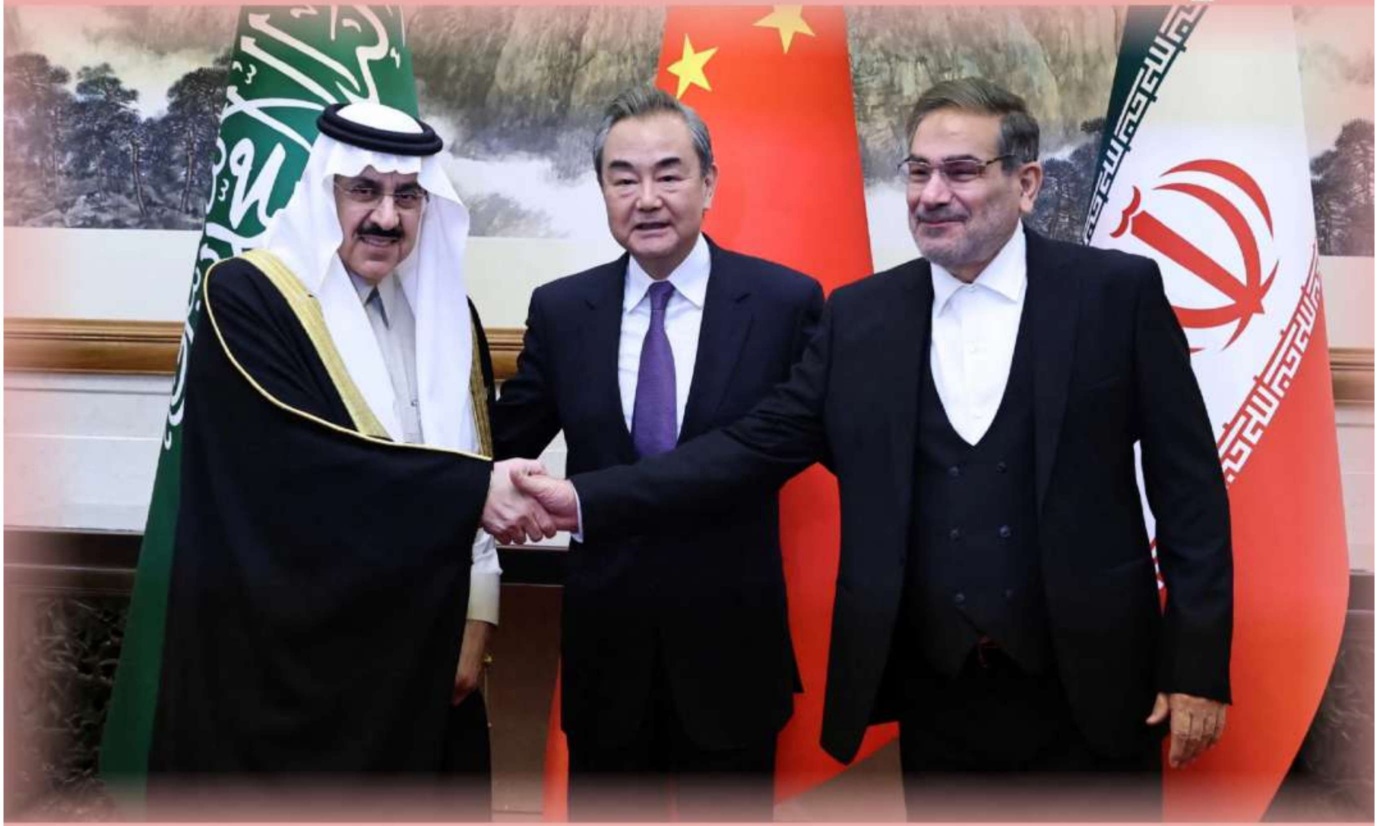

- महाराष्ट्र में लव जिहाद के एक लाख से अधिक मामले
- नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन
- जर्मनी के चर्च में आतंकी हमला
- सऊदी अरब के विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में लव जिहाद के एक लाख से अधिक मामले 04
मुसलमानों को भाजपा के नजदीक लाने के लिए 'मोदी मित्र' 06
जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर 08
सांप्रदायिक भावना भड़काने के आरोप में मौलाना पर मुकदमा दर्ज 09
रमजान के बाद शुरू होगा अयोध्या की मस्जिद का निर्माण 10

विश्व

अफगानिस्तान में गवर्नर की हत्या 12
बलूचिस्तान में पुलिस ट्रक में धमाका 13
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप 14
जर्मनी के चर्च में इस्लामिक आतंकियों की गोलाबारी से आठ मरे 15
बांग्लादेश में धमाके से 28 मरे 16

पश्चिम एशिया

ईरान और सऊदी अरब में समझौते से विश्व की राजनीति में नया मोड़ 17
नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन 20
ईरान में प्रदर्शनकारियों को आम माफी की घोषणा 21
तुर्की को सऊदी अरब की सहायता 21
सऊदी अरब, कतर और मिस्र अस्त्र-शस्त्रों के दस बड़े खरीदारों में शामिल 22

अन्य

मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में न्यूज चैनल पर जुर्माना 23
सऊदी अरब के विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा 23
सन्यासी के देवबंद में प्रवेश पर रोक 24
अलीगढ़ में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया 24
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष का निधन 25

सारांश

चीन की कूटनीति ने अमेरिका के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। जिस तरह से चीन की राजधानी बीजिंग में दो पुराने दुश्मन देशों सऊदी अरब और ईरान ने आपस में डिप्लोमेटिक संबंध फिर से स्थापित करने की घोषणा की है, उसने विश्व की मुस्लिम राजनीति की धारा को ही बदल दिया है। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है। इसका बुनियादी कारण यह है कि सऊदी अरब का शासक परिवार सुन्नी संप्रदाय के वहाबी विचारधारा से संबंधित है। जबकि ईरान कट्टर शिया देश है। मुसलमानों के इन दोनों संप्रदायों के बीच प्रारंभ से ही जबर्दस्त द्वेष रहा है। शियाओं का आरोप है कि उनके नौ इमामों की हत्या सुन्नी खलिफाओं ने की थी। मुसलमानों के इन दोनों संप्रदायों के बीच हालांकि पैगम्बर और कुरान पर सहमति है। लेकिन दोनों के कलमे (इस्लाम के मूल मंत्र) में मूलभूत अंतर है। इसके अतिरिक्त शिया इस्लाम के पहले तीन खलीफाओं को भी मान्यता नहीं देते। उनका आरोप है कि पैगम्बर-ए-इस्लाम ने अपने दामाद हजरत अली को अपना खलीफा बनाने की वसीयत की थी, जिसका पालन उनके ससुर अबु बकर ने नहीं किया और उन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इस्लामिक जगत भी शिया और सुन्नी खेमों में प्रारंभ से बंटा रहा है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मुस्लिम जगत में अपने प्रभाव को बढ़ाने और इजरायल को अरब जगत में स्थापित करने के लिए 'अब्राहम समझौते' की शुरुआत की थी। इस समझौते के तहत सात अरब देशों ने इजरायल को मान्यता दी थी। अरब जगत में प्रारंभ से ही ब्रिटेन और अमेरिका का वर्चस्व रहा है। मगर चीन ने हाल ही में अपनी कूटनीति से इस वर्चस्व को मिट्टी में मिला दिया है। अरब जगत में चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण भारत के लिए भी व्यापारिक और राजनीतिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना बनाई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यह दावा किया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में देश के मुसलमानों को प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए 25 अप्रैल से एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत देश के 65 मुस्लिम बहुल जिलों में 'मोदी मित्रों' की नियुक्ति की जाएगी, जोकि मुसलमानों के घर-घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री की अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भाजपा की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

बरेलवी मुस्लिम संप्रदाय के मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ मुरादाबाद के एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रजा ने गत दिनों यह कहा था कि खालिस्तान की मांग करना अगर गलत है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, वही हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई हो और उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मुकदमे दर्ज किए जाएं। अगर मुसलमान भी खड़े होकर मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दें, तो क्या होगा? इसके साथ ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनकी इस मांग का विरोध हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने किया है और रजा के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

हाल ही में अफगानिस्तान में सुन्नी इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों में भारी तेजी आई है। इस संगठन के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के एक प्रांत बल्ख के गवर्नर मुल्ला मोहम्मद दाउद मुजम्मिल की हत्या कर दी है। गौरतलब है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हुए हैं, उनके खिलाफ आईएसआईएस ने खूनी संघर्ष छेड़ दिया है। अफगान सेना ने हाल ही में इस संगठन के खुरासान चैप्टर के प्रमुख और उसके सहयोगियों की हत्या कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि आईएसआईएस की आड़ में विदेशी शक्तियां तालिबान सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रच रही हैं।

महाराष्ट्र में लव जिहाद के एक लाख से अधिक मामले

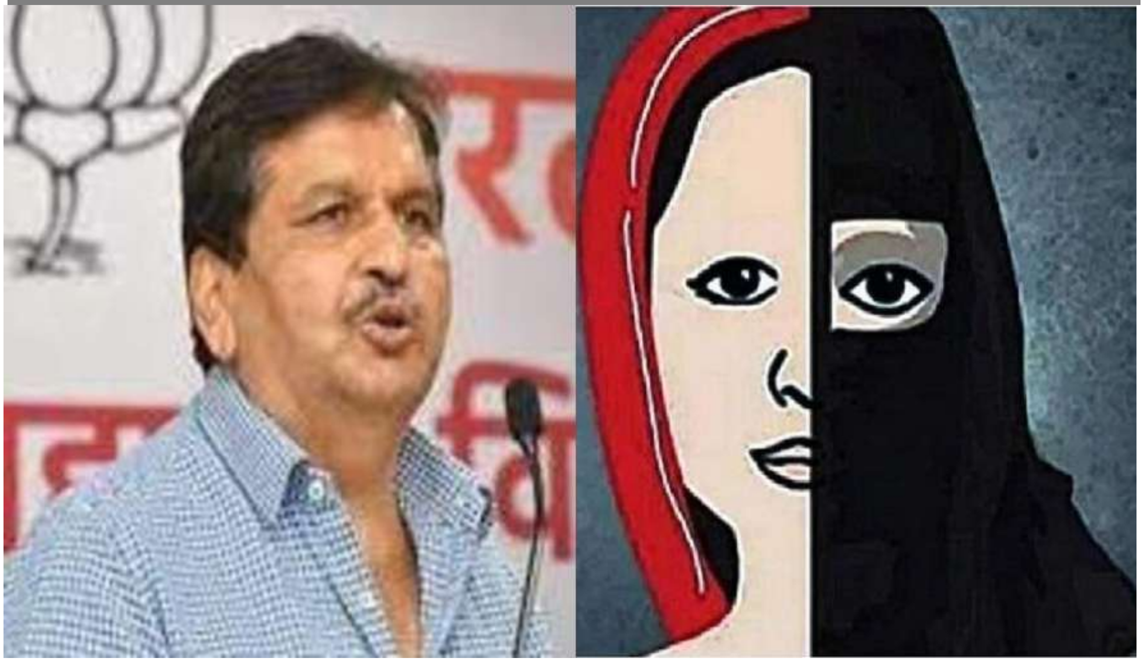

रोजनामा सहारा (10 मार्च) के अनुसार महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने विधानसभा में यह जानकारी दी कि महाराष्ट्र मे लव जिहाद से संबंधित एक लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं के खिलाफ राज्य के अनेक भागों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, ताकि भविष्य में श्रद्धा वॉकर जैसा कोई मामला न हो। इस संबंध में उचित कदम उठाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, इसलिए अंतरधार्मिक विवाह कमेटी बनाई गई है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर महीने में महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि उसने विभिन्न धर्मों और जातियों से संबंधित विवाहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि विभिन्न धर्मावलंबियों और जातियों के बीच हुई शादियों की निगरानी परिवार समन्वय समिति करेगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (11 मार्च) के अनुसार इस मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि ये आंकड़े फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह की फर्जी जानकारी फैलाकर राजनीति करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना भाजपा का पुराना खेल है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जो आंकड़े मिले हैं वे 4600 अंतरधार्मिक शादियों के हैं। ये आंकड़े सिर्फ हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच के नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों के बीच हुई शादियों के हैं और ये शादियां लड़की और लड़के की मर्जी से हुई हैं। इसमें लव जिहाद का कोई पहलू ही नहीं है। उनके इस बयान पर भाजपा के विधायक योगेश सागर, आशीष शेलार, जयकुमार रावल और गुलाब राव पाटिल ने आपत्ति की। उन्होंने आरोप

लगाया कि आव्हाड जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए वे जानबूझकर सच्चाई को छिपा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि लोढ़ा ने क्योंकि सदन को गुमराह किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के नेता आशीष शेलार ने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार से कानून बनाने की मांग की। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक रईस शेख ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें लोढ़ा के आंकड़ों को चुनौती दी गई है। शेख ने पत्रकारों को बताया कि मंत्री ने सदन को गुमराह किया है, इसलिए उन्हें अब उच्च न्यायालय जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी।

औरंगाबाद टाइम्स (11 मार्च) के अनुसार लव जिहाद के मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा में उस समय जोरदार हंगामा हुआ, जब समाजवादी पार्टी के नेता अबु आसिम आजमी ने यह आरोप लगाया कि लव जिहाद से संबंधित मामलों के बारे में मंत्री ने सदन को गलत सूचनाएं दी हैं, इसलिए उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लव जिहाद का कोई मामला ही नहीं है। भाजपा सरकार सांप्रदायिक भावनाओं को राजनीतिक उद्देश्य से भड़का रही है। इस पर भाजपा के आशीष शेलार ने आजमी को टोकते हुए कहा कि मंत्री क्यों माफी मांगें? हिंदू बहन-बेटियों की रक्षा के लिए हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर आजमी और भाजपा के विधायकों में जोरदार झड़पें हुई। आजमी ने आरोप लगाया कि समाज में नफरत पैदा करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं। जबकि सच्चाई से इनका कोई संबंध नहीं है।

इससे पूर्व मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने यह दावा किया था कि राज्य में लव जिहाद के एक लाख मामले सामने आए हैं। इस पर विपक्ष और भाजपा के नेताओं के बीच जोरदार झड़पें हुई। समाजवादी पार्टी के एक विधायक रईस शेख ने राज्य सरकार द्वारा परिवार समन्वय समिति बनाने के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और यह दावा किया है कि यह कमेटी एक विशेष मजहब के लोगों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है, जोकि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

रईस शेख ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि यह कमेटी अंतरधार्मिक शादियों को हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई है और इसका लक्ष्य लव जिहाद के खिलाफ विधान सभा में विधेयक पेश करना है। शेख ने कहा कि यह कमेटी किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर किसी भी विवाह से संबंधित मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, जोकि दंपत्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप है। संविधान में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि दो व्यस्क व्यक्ति आपसी सहमति से शादी कर सकते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 मार्च) के अनुसार रईस शेख ने महाराष्ट्र विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद से संबंधित एक लाख मामलों का विधानसभा में मंत्री ने जो उल्लेख किया है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस गलत जवाब के कारण काफी भ्रांति उत्पन्न हुई है। अपने नोटिस में उन्होंने यह दावा किया है कि मंत्री ने सदन को गलत सूचनाएं देकर गुमराह किया है। इससे सदन की साख पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और राज्य के कुछ वर्गों की भावनाओं को आघात पहुंचा है।

औरंगाबाद टाइम्स (18 मार्च) के अनुसार लव जिहाद और धर्मांतरण पर बनाए गए कानूनों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की। वकील इंदिरा जय सिंह ने अदालत को बताया कि पिछली सुनवाई में अदालत ने सभी राज्यों को धर्मांतरण के

खिलाफ बनाए गए कानूनों पर जानकारी देने का निर्देश दिया था। लेकिन अभी तक सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही इस संबंध में जानकारी दी है। अन्य राज्यों ने अभी तक इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी है। अदालत में वकीलों ने यह मांग की कि लव जिहाद के कानून पर तत्काल स्थगन आदेश जारी किया जाए। लेकिन न्यायालय ने उनके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अदालत इस संदर्भ में शीघ्र ही सुनवाई करेगी।

अदालत में वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह ने बताया कि अब तक दस राज्य सरकारें लव जिहाद के खिलाफ कानून बना चुकी हैं और अन्य राज्य भी इस संदर्भ में कानून बनाने पर विचार कर रही हैं। महाराष्ट्र में इस तरह का कानून बनाने के लिए राज्यभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अदालत को इस संदर्भ में स्थगन आदेश जारी करने का शीघ्र ही निर्णय करना चाहिए, ताकि अन्य राज्यों को भी ऐसे कानून बनाने से रोका जा सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के बाद ही अदालत स्थगन आदेश जारी करने के बारे में कोई फैसला करेगी। अदालत में जमीयत उलेमा की ओर से वकील शाहिद नदीम, सैफ जिया एवं मुजाहिद अहमद आदि भी मौजूद है। गौरतलब है कि जमीयत उलेमा सहित कुछ मुस्लिम संगठनों ने देश के विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए लव जिहाद के कानून को अदालत में चुनौती दी है। ■

मुसलमानों को भाजपा के नजदीक लाने के लिए 'मोदी मित्र'

सियासत (17 मार्च) के अनुसार भाजपा ने लोकसभा के आगामी चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने हेतु मुसलमानों को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। भाजपा देश के 65 मुस्लिम बहुल जिलों में 5000 मुसलमानों को 'मोदी मित्र' बनाएगी, जोकि अपने-अपने क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और असम के मुस्लिम बहुल जिले शामिल हैं। इस योजना की शुरुआत 25 अप्रैल से हो रही है और यह एक वर्ष तक चलेगी। भाजपा ने 15 मार्च से 'सूफी संवाद' महाअभियान भी शुरू किया है, जिसका लक्ष्य सूफियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को भाजपा से जोड़ना है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार इन 'मोदी मित्रों' के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में हर मुस्लिम मतदाता के घर से संपर्क किया जाएगा। पहले यह अभियान जिला स्तर पर और बाद में ब्लॉक स्तर पर चलाया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश को जनता तक पहुंचाकर उन्हें भाजपा के साथ जोड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। इन मुस्लिम बहुल जिलों में उत्तर प्रदेश के कैराना, रामपुर, सहारनपुर, बरेली, नगीना, मुरादाबाद और मेरठ को शामिल किया गया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के बसीरहाट, कृष्णानगर, मुर्शिदाबाद, बरहामपुर, रायगंज, डायमंड हार्बर और जंगीपुर शामिल हैं। वहीं केरल के वायनाड, कासरगोड, कोट्टयम, मल्लपुरम आदि जिले शामिल हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के पांच जिलों के साथ-साथ लद्दाख में भी मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष रणनीति अपनाई गई है।

भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे केरल के मुस्लिम और ईसाई परिवारों के साथ संपर्क बढ़ाएं। इस रणनीति के तहत भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम त्योहारों पर मुसलमानों से संपर्क करके उन्हें विशेष समारोह में निमंत्रण भी दे रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा

के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण की ओर जो विशेष ध्यान दिया है, उसके कारण समाज के सभी वर्गों का भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है और इनमें मुसलमान भी शामिल हैं। हाल ही में हुए लोकसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के रामपुर जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार को जो भारी सफलता मिली है, वह इस बात का साफ संकेत है। हम मुस्लिम मतदाताओं के पास पहुंचकर उन्हें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को उन मतदाताओं तक पहुंचना है, जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पूरे देश में कोई भी घर भाजपा के कार्यकर्ताओं के संपर्क से अछूता न रहे। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हर मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र में जिला और ब्लॉक स्तर पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं के संगठन को मजबूत बनाएंगे। इनमें से प्रत्येक कार्यकर्ता से यह आशा की जाती है कि आगामी चुनाव में वह कम-से-कम दस मुस्लिम वोट भाजपा को दिलाए। पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस दिशा में जो प्रयास किया था, उसकी सफलता के बाद देश स्तर पर यह अभियान चलाने का फैसला किया गया है।

सियासत (11 मार्च) के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की भारी सफलता के बाद पार्टी को यह आशा है कि वह कर्नाटक के चुनाव में अपनी सत्ता को बरकरार रखेगी और आंध्र प्रदेश में वह वाईएसआर कांग्रेस से सत्ता छीनने में सफल होगी। तमिलनाडु में भी पार्टी की नजर सत्ता प्राप्त करने पर है। लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सत्ता प्राप्त करना आसान नहीं है। क्योंकि, इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों का संगठन काफी मजबूत है और जनता में उनकी लोकप्रियता भी बरकरार है। जगन मोहन रेड्डी और एम.के. स्टालिन की सरकारें आम लोगों का दिल जीत चुकी हैं। तेलंगाना में भी भाजपा कदम जमाने का प्रयास कर रही है। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के तेवर काफी आक्रामक हैं। लेकिन मुनुगोडे विधानसभा के उपुचनाव में बीआरएस की सफलता के बाद भाजपा के मंसूबों को धक्का लगा है। इसलिए भाजपा को अब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जबकि तेलंगाना में विजय प्राप्त करने के लिए उसे जबर्दस्त संघर्ष करना होगा। तेलंगाना के बाहर कदम जमाना बीआरएस के लिए आसान नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा विरोधी मंच के लिए उम्मीद की किरण हैं। जबकि दक्षिण में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, जो कि भगवा पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं। भाजपा ने 2019 में कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटों में से 25 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। जबकि तेलंगाना से भाजपा के चार सांसद हैं। लेकिन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पिछली बार भाजपा का कोई सांसद नहीं चुना गया है। केरल में अब तक सीपीआईएम नीत एलडीएफ और कांग्रेस नीत यूडीएफ के बीच संघर्ष होता रहा है। वहां अभी तक कोई भी अन्य पार्टी अपना रंग नहीं जमा पाई है।

जामिया मिलिया इस्लामिया के नए चांसलर

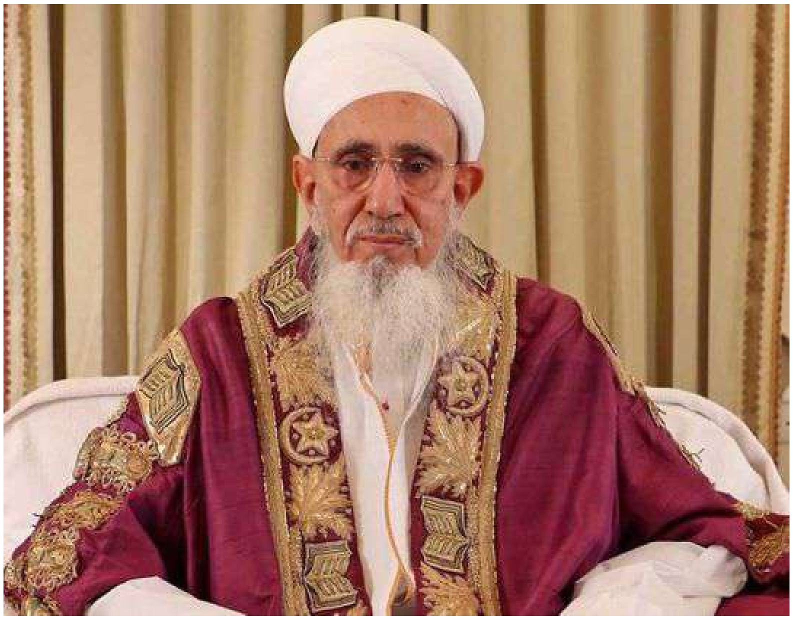

इंकलाब (14 मार्च) के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया अंजुमन (कोर्ट) की बैठक में डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पांच वर्ष के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया का नया चांसलर (अमीर-ए-जामिया) चुना गया है। जामिया कोर्ट में कुल 45 सदस्य हैं, जिनमें तीन सांसद भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व डॉ. नजमा हेपतुल्ला जामिया मिलिया इस्लामिया की चांसलर थीं और उनका पांच वर्ष का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। अब उनका स्थान डॉ. मुफद्दल सैफुद्दीन लेंगे। डॉ. मुफद्दल 2014 से दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। उन्हें अब तक अनेक अवार्ड भी मिल चुके हैं। उन्हें दुनिया के 500 सबसे असरदार मुस्लिम नेताओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने जामिया अल-अजहर और काहिरा यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है।

उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी 2023 को मुफद्दल सैफुद्दीन ने मुंबई में अल जामिया तुस-सैफियाह के नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। इस समारोह में मोदी ने सैयदना परिवार के साथ अपने पुराने संबंधों का भी उल्लेख किया था। सैफुद्दीन ने यमन में शिक्षा के प्रसार की विशेष योजना शुरू की थी। वे उर्दू और अरबी में कविता भी लिखते हैं।

रोजनामा सहारा (14 मार्च) के अनुसार लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने सैयदना को जामिया मिलिया इस्लामिया का चांसलर चुने जाने का स्वागत किया है और कहा है कि दुनिया के सबसे असरदार मुसलमानों में से डॉ. सैयदना को चांसलर चुना जाना स्वागत योग्य है। इससे मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार में विशेष रूप से सहायता मिलेगी। इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में कहा है कि डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन सूरत के ऐतिहासिक दाउदी बोहरा शिक्षा संस्थान अल जामिया तुस-सैफियाह के भी छात्र रहे हैं। उन्होंने इस्लाम पर कई पुस्तकें लिखी हैं। वे दुनिया भर में मुसलमानों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी चला रहे हैं।

सांप्रदायिक भावना भड़काने के आरोप में मौलाना पर मुकदमा दर्ज

इंकलाब (14 मार्च) के अनुसार मुरादाबाद के थाना नागफनी में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलना तौकीर रजा खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मौलाना ने गत दिनों मदरसा जामिया अशरफिया में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में मांग की थी कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। क्योंकि ये मांग संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि इस मांग से प्रेरित होकर मुसलमान युवक भी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करने लगें। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सही हैं, तो फिर खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को देश का हिस्सा समझता हूं। मगर कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं, जोकि मुस्लिम दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे इस तरह से हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जो कातिल हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए जाते? ये दोहरी नीति क्यों? सरकार की इस नीति को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

समाचारपत्र का कहना है कि मौलाना के इस बयान को विभिन्न टीवी चैनलों ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला बताकर उसे वायरल किया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौलाना के खिलाफ धारा 153ए, 295ए और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर के इस्लामिक संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की है कि इस मुकदमे को फौरन वापस लिया जाए। मुकदमा दर्ज होने के बाद मौलाना तौकीर रजा खान ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि हम हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, तो हमारे खिलाफ ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर मेरे बयान में कुछ गलत है, तो मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। मेरे उपर देशद्रोह और यूएपीए जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पूर्व मौलाना ने हरियाणा में दो मुसलमान युवकों की हत्या पर रोष प्रकट करते हुए प्रधाानमंत्री नरेन्द्र मोदी से यह मांग की थी कि वे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं।

हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बरेली में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मौलाना

तौकीर रजा को देश का गद्दार बताया और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। साध्वी ने कहा कि यह मौलाना 2010 के दंगों का सबसे बड़ा आरोपी है और उसके मकान पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और यह हमेशा रहेगा। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान बना तो, कुछ लोग हमारा खून पीने के लिए हिंदुस्तान में रूक गए।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 मार्च) के अनुसार तेलंगाना भाजपा के निलंबित विधायक टी. राजा सिंह के खिलाफ अहमदनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे के अनुसार राजा सिंह को दस मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाए जाने से संबंधित एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। कहा जाता है कि इस कार्यक्रम में उनका भाषण मुस्लिम विरोधी था। इसके बाद कुछ मुसलमानों ने अहमदनगर जिले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। श्रीरामपुर थाना के इंचार्ज इंस्पेक्टर हर्षवर्धन गवली ने बताया कि राजा सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व फरवरी महीने में भी राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक ऐसा ही मुकदमा दर्ज किया गया था। अगस्त 2022 में उन्हें तेलंगाना पुलिस ने इस्लाम और पैगम्बर के खिलाफ एक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। ■

रमजान के बाद शुरू होगा अयोध्या की मस्जिद का निर्माण

सियासत (9 मार्च) के अनुसार अयोध्या के समीप धन्नीपुर गांव में बाबरी मस्जिद के बदले में एक नई मस्जिद के निर्माण के लिए सरकार ने जो भूखंड दिया है, उसका निर्माण कार्य रमजान महीने के बाद शुरू होने की संभावना है। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा धन्नीपुर गांव में मस्जिद परिसर के नक्शे की मंजूरी दे दी गई है। इस बात की पुष्टि जिलाधिकारी और अयोध्या विकास

प्राधिकरण के अध्यक्ष नितीश कुमार ने की है। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के निर्माण से संबंधित जो योजनाएं अधिकरण के पास विचाराधीन थीं, उसे मंजूरी दे दी गई है। आवश्यक सरकारी कार्यवाही के बाद मंजूर किए गए नक्शे को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा।

वक्फ बोर्ड ने कहा है कि रमजान का महीना गुजरने के बाद वक्फ बोर्ड इस नक्शे पर निर्माण कार्य शुरू करने के संबंध में फैसला करेगा। धन्नीपुर में मस्जिद के निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड ने जो ट्रस्ट इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन बनाया है, उसके सचिव अतहर हुसैन सिद्दीकी ने कहा है कि रमजान के बाद हम इस फाउंडेशन की एक बैठक बुला रहे हैं, जिसमें इस मस्जिद के निर्माण को शुरू करने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

गौरतलब है कि रमजान का पवित्र महीना 22 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 9 नवंबर 2019 को विवादित ढांचे के स्थान पर राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुनाया था और साथ ही सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह बाबरी मस्जिद के विकल्प के रूप में मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या जिले में पांच एकड़ का प्लॉट अलॉट करे। इसके बाद राज्य सरकार ने धन्नीपुर गांव में मस्जिद के नए परिसर के निर्माण के लिए एक भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलॉट किया था। वक्फ बोर्ड का कहना है कि वह इस नई मस्जिद को पुरानी बाबरी मस्जिद से संबंधित नहीं करना चाहता, जिसे छह दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। धन्नीपुर में निर्माण किए जाने वाले मस्जिद परिसर का नाम किसी मुगल बादशाह के नाम पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस परिसर और मस्जिद का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मौलवी अहमद उल्लाह शाह फैजाबादी के नाम पर रखा जाएगा। इस परिसर में एक मस्जिद, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर और म्यूजियम शामिल होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने पिछले दिनों यह दावा किया था कि शरीयत के अनुसार किसी भी मस्जिद के बदले में कोई भूखंड प्राप्त नहीं किया जा सकता।

अफगानिस्तान में गवर्नर की हत्या

सालार (10 मार्च) के अनुसार आईएसआईएस के आतंकवादियों ने उत्तरी अफगानिस्तान के प्रदेश बल्ख के गवर्नर मुल्ला मोहम्मद दाउद मुजम्मिल की एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी है। उनके साथ कुछ अफगानिस्तान सरकार के पदाधिकारी भी मारे गए हैं। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि आईएसआईएस के एक आत्मघाती हमलावर ने यह धमाका उस समय किया जब गवर्नर उच्चाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रवक्ता के अनुसार दाउद मुजम्मिल तालिबान के उच्च सैनिक अधिकारियों में शामिल थे और उनके ईरान के पासदारान-ए-इंकलाब के साथ गहरे संबंध थे।

दाउद मुजम्मिल पहले उपगृह मंत्री थे और फिर उन्हें बल्ख का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व वे नंगरहार प्रांत के गवर्नर के तौर पर भी काम कर चुके थे। तालिबान के प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें दाउद मुजम्मिल की विशेष भूमिका थी और वे आईएसआईएस के आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान की कमान संभाले हुए थे। जबसे अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हुए हैं, आतंकवादी संगठन आईएसआईएस उनके खिलाफ हिंसक अभियान छेड़े हुए है। अफगान सरकार ने हाल ही में यह दावा किया था उसने आईएसआईएस के 11 आतंकियों की हत्या कर दी है। अब तक आईएसआईएस अफगानिस्तान में 1100 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है और उसके आतंकी विशेष रूप से मस्जिदों और शिया बहुल क्षेत्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। जनवरी महीने में आईएसआईएस के एक आत्मघाती हमलावर ने अफगान विदेश मंत्रालय में

घुसकर स्वयं को विस्फोट से उड़ा लिया था। इस घटना में विदेश मंत्रालय के दस अधिकारी मारे गए थे।

रोजनामा सहारा (1 मार्च) के अनुसार तालिबान सरकार ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान की सेना ने आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर के प्रमुख ऐजाज अहमद अहंगर को उसके तीन अन्य साथियों सहित मार दिया है। उसके दो अन्य साथी भी मारे गए हैं, जिनमें कारी फतह भी शामिल है, जोकि इस्लामिक स्टेट का ऑपरेशन कमांडर था। गौरतलब है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अहंगर द्वारा इस इस्लामिक आतंकी संगठन की हिंसक कार्रवाईयों का संचालन किया जाता था और पिछले दिनों काबुल के गुरुद्वारा में जो धमाका हुआ था, उसकी योजना भी इसी व्यक्ति ने बनाई थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन आतंकवादियों के मारे जाने से अफगानिस्तान में हो रही हिंसा में कमी आएगी।

इत्तेमाद (6 मार्च) के अनुसार फिलीपींस में इस्लामिक आतंकियों ने एक गवर्नर और चार उच्चाधिकारियों की हत्या कर दी है। इस संबंध में चार संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका संबंध एक इस्लामिक आतंकी संगठन से बताया जाता है। इस घटना की निंदा फिलीपींस के राष्ट्रपति ने की है और कहा है कि हम किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शेंगे। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस्लामिक आतंकवादी तब गवर्नर के महल में दाखिल हुए, जब वे दर्शकों से मुलाकात कर रहे थे। आक्रमणकारियों ने आते ही अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें गवर्नर सहित कई लोग मारे गए। इस हमले के बाद आतंकवादी एक वाहन में सवार होकर भागने में सफल रहे। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें दो पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। इनमें से एक आक्रमणकारी सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया। सरकारी प्रवक्ता ने इस बात की घोषणा नहीं की कि आक्रमणकारियों का संबंध किस इस्लामिक आतंकी संगठन से था। फिलीपींस में मुस्लिम आतंकवादी काफी समय से सक्रिय हैं और वे कई हिंसक कार्रवाईयां कर चुके हैं।

बलूचिस्तान में पुलिस ट्रक में धमाका

अवधनामा (7 मार्च) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला बोलान में बलूचिस्तान पुलिस के एक ट्रक में धमाका हुआ, जिसमें कम-से-कम 10 पुलिसकर्मी मारे गए और 13 घायल हो गए। बोलान जिले के पुलिस कप्तान ने बताया कि यह धमाका बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी के आत्मघाती

हमलावरों ने किया है। इस संगठन से संबंधित दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने ट्रक के नजदीक आते ही स्वयं को विस्फोटक पदार्थों से उड़ा लिया, जिसमें कम-से-कम 10 लोग मारे गए।

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार मरने वालों की संख्या 15 बताई जा रही है। बलूचिस्तान के गृहमंत्री मीर जिया उल्लाह लंगौ ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में इमरजेंसी की घोषणा की गई है और उन्होंने आतंकवादियों को कुचलने के लिए फेडरल सरकार से अर्द्धसैनिक बलों की मदद मांगी है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर अब्दुल कुद्दुस बिजेंजो ने कहा है कि इस हमले के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है, जोकि बलूचिस्तान की जनता को पिछड़ा रखना चाहते हैं और पाकिस्तान को खंडित रखना चाहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाल ही में पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवाद की एक नई लहर शुरू हुई है। इनमें से अधिकांश घटनाओं में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व बलूचिस्तान में इस जिहादी संगठन के हमलों के चलते एक महीने के अंदर कम-से-कम 22 लोग मारे गए हैं, जिनका संबंध सेना और पुलिस से बताया जाता है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि जिला बोलान में फ्रंटियर फोर्स की एक चेकपोस्ट पर कुछ अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने हमला किया। इस हमले में तीन पुलिस अधिकारी मारे गए और हमलावर काफी अस्त्र-शस्त्र लूटकर अपने साथ ले गए। पिछले महीने बलूचिस्तान के जिला पंजगुर स्थित ईरान की सीमा पर भी आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था, जिसमें 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इस हमले के बाद आतंकवादी भागकर ईरान चले गए थे। पाकिस्तान सरकार ने ईरान से अनुरोध किया है कि वह इन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप

इत्तेमाद (10 मार्च) के अनुसार मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को जांच आयोग ने करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोपी करार दिया है। उन्हें दी जाने वाली सजा की घोषणा बाद में की जाएगी। मोहिउद्दीन साल 2020-21 में 17 महीने तक मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे थे। गत वर्ष नवंबर महीने में हुए चुनाव में वे अनवर इब्राहिम से हार गए थे। इसके बाद नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को यह निर्देश दिया था कि मोहिउद्दीन यासीन ने अपने कार्यकाल में जो अरबों डॉलर खर्च वाली सरकारी योजनाओं की मंजूरी दी थी, उनके खातों की जांच की जाए। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरकारी फंड में भ्रष्टाचार किया है और करोड़ों डॉलर अपने संबंधियों के खातों में जमा करवाए हैं।

मोहिउद्दीन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के तहत विरोधी राजनेता झूठे आरोपों में फंसा रहे हैं। जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मोहिउद्दीन का आरोप सरासर झूठा है। उनके दो पुराने सहयोगियों ने ही जांच आयोग के सामने उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। इसके बाद इस मामले की बारिकी से जांच की गई। मोहिउद्दीन के साथ-साथ उनके सहयोगी और उनके रिश्तेदारों के सारे बैंक खातों को फ्रिज कर दिया गया है। प्रयवेक्षकों का अनुमान है कि इस वर्ष के मध्य में मलेशिया के छह राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उन पर इस मुकदमे का प्रभाव पड़ने की संभावना है। मलेशिया के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के प्रमुख आजम बाकी ने कहा है कि जब मोहिउद्दीन को सजा सुनाई जाएगी, उस समय उनके द्वारा किए गए घोटालों का भी पर्दाफाश किया जाएगा।

जर्मनी के चर्च में इस्लामिक आतंकियों की गोलाबारी से आठ मरे

इंकलाब (11 मार्च) के अनुसार जर्मनी के नगर हैम्बर्ग के एक चर्च में जब प्रार्थना की जा रही थी, तो एक सशस्त्र हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में हमलावर सहित आठ लोग मारे गए और एक दर्जन के लगभग लोग घायल हो गए। घायलों में से अधिकांश की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस के प्रवक्ता ने यह संदेह व्यक्त किया है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। जर्मन गुप्तचर विभाग इस हमले के दोषी व्यक्तियों का सुराग लगाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर के संबंध में किसी भी तरह की सूचना मीडिया को देने से इंकार कर दिया है और कहा है कि इससे इस घटना की जांच में बाधा आ सकती है।

जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इस घटना की निंदा की है और इसके पीछे इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ होने का संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने इस धमाके में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि

जब तक जर्मन पुलिस इस पूरी घटना की भूमिका और उससे जुड़े हुए लोगों का सुराग नहीं लगा लेती, तब तक वे इस संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। जर्मनी की सरकार हथियारों की खरीद के नियमों को कड़ा बनाने का प्रयास कर रही है। जर्मनी के अखबारों के अनुसार जो लोग मारे गए हैं, उनका संबंध एक ईसाई संप्रदाय जेहोवा विटनेसेस से है। जर्मनी में इस संप्रदाय से संबंधित ईसाईयों की संख्या दो लाख के करीब बताई जाती है। इस संगठन के तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं। यह एक शांतिप्रिय संगठन है और शांतिपूर्ण ढंग से ईसाईयत का प्रचार व प्रसार करने में विश्वास रखता है। गौरतलब है कि जर्मनी में कई इस्लामिक संगठन सक्रिय हैं और गत दो वर्षों में वे कम-से-कम एक दर्जन से अधिक हिंसक कार्रवाईयां कर चुके हैं।

बांग्लादेश में धमाके से 28 मरे

रोजनामा सहारा (10 मार्च) के अनुसार गत एक सप्ताह में बांग्लादेश में हुए तीन विस्फोटों में कम-से-कम 28 लोग मारे जा चुके हैं और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा धमाका ढाका के सबसे फैशनेबल क्षेत्र में हुआ जिसमें कम-से-कम 18 व्यक्ति मारे गए और 140 से अधिक लोग घायल हो गए। इससे पूर्व ढाका में ही कपड़े के एक बाजार में बम फटने से तीन व्यक्ति मारे गए और एक दर्जन घायल हो गए।

इससे एक दिन पूर्व सीताकुंडा के एक कारखाने में हुए धमाके में सात लोग मारे गए और कम-से-कम 25 घायल हो गए। बांग्लादेश सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है। एक पुलिस प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की कि हाल ही में बांग्लादेश में आतंकवादियों की गतिविधियों में तेजी आई है। गुप्तचर विभाग इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन धमाकों के पीछे किसका हाथ है। अभी तक इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।

सियासत (7 मार्च) के अनुसार बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर में आग लग जाने के कारण 12 हजार झुग्गियां जल गईं और 23-24 हजार लोग बेघर हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के शरणार्थी आयुक्त मिजानुर रहमान ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में यह आग लगी थी। इस आग के कारण 35 मस्जिदें और 51 मदरसे जल गए। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी व्यक्ति के मरने की कोई सूचना नहीं है।

गौरतलब है कि इस समय म्यांमार से भागकर आए 12 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश 2017 में म्यांमार की रखाइन प्रदेश से म्यांमार की सैनिक कार्रवाईयों के बाद भागकर बांग्लादेश आए थे। बांग्लादेश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष इन शरणार्थी शिविरों में 222 आग लगने की घटनाएं हुई, जिनमें डेढ़ सौ से अधिक लोग मारे गए और एक लाख के लगभग लोग बेघर हो गए।

ईरान और सऊदी अरब में समझौते से विश्व की राजनीति में नया मोड़

विश्व की राजनीति में अब एक नया मोड़ आ गया है। चीन के प्रयास से विश्व के दो महत्त्वपूर्ण मुस्लिम देशों ने पुरानी शत्रुता को भुलाकर आपस में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। पर्यवेक्षकों के अनुसार चीन कूटनीति में अमेरिका और इजरायल से बाजी मार गया है। मुस्लिम जगत में गत कई दशकों से अमेरिका द्वारा इजरायल को जमाने का जो प्रयास किया जा रहा था, वह अब मिट्टी में मिल गया है। खास बात यह है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियां भी इस घटनाक्रम का कोई संकेत देने में पूरी तरह से विफल रही हैं।

उर्दू के लगभग सभी अखबारों ने इस समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और इस पर संपादकीय भी लिखे हैं।

इत्तेमाद (11 मार्च) के अनुसार ईरान और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक संबंध की शुरुआत करने की विधिवत घोषणा की गई है। यह समझौता चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही गुप्त वार्ता के बाद सामने आया है। ईरान और सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान और सऊदी अरब ने दो महीने के अंदर दोनों देशों में पुनः दूतावास खोलने पर सहमति व्यक्त की है। इस खबर की पुष्टि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी 'इरना' और सऊदी अरब की संवाद समिति 'सऊदी प्रेस एजेंसी' ने भी की है। दोनों ने इस समझौते का विवरण प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

चीनी सरकारी मीडिया ने इस समझौते की घोषणा तुरंत नहीं की। मगर उसने एक फोटो प्रकाशित किया, जिसमें ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी को सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद बिन

मोहम्मद अल-ऐबन और चीन के वरिष्ठ राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात करते हुए दिखाया गया है। चीन ने इन दोनों देशों के बीच हुए समझौते का सवागत किया है। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने चीन का दौरा किया था और इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दिसंबर महीने में सऊदी अरब का दौरा किया था। बताया जाता है कि इन दोनों देशों को एक दूसरे के समीप लाने में चीन ने विशेष भूमिका अदा की है।

अवधनामा (11 मार्च) के अनुसार अलजजीरा के रिपोर्टर अली हाशिम ने दावा किया है कि पिछले दो वर्ष से सऊदी अरब और ईरान के बीच बगदाद में गुप्त वार्ता हो रही थी। अब चीन में होने वाली बैठक इस संदर्भ में निर्णायक साबित हुई है। गौरतलब है कि सऊदी अरब ने 2016 में शिया विद्वान निम्र अल निम्र को फांसी दे दी थी, जिसके जवाब में ईरान के प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के दूतावास पर हमला करके आग लगा दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध समाप्त हो गए थे।

इत्तेमाद (12 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ताना संबंधों की शुरुआत के पीछे चीन का हाथ है और इससे विश्व की राजनीति में नया मोड़ आएगा। समाचारपत्र के अनुसार ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन में छह से दस मार्च तक गुप्त बातचीत हुई थी। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि इस्लामिक एकता की दिशा में यह महत्त्वपूर्ण कदम है। चीन के राजनयिक वांग यी के अनुसार चीन ने एक अच्छे अतिथि और विश्वसनीय दोस्त की भूमिका निभाई है।

समाचारपत्र के अनुसार इस्लामिक जगत में वर्चस्व को लेकर सऊदी अरब और ईरान के बीच पिछले पांच दशक से शीत युद्ध जारी था। 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद इसमें और भी बढोतरी हुई थी। सऊदी अरब और अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद को हटाना चाहते थे। जबकि ईरान उनकी रक्षा के लिए अड़ गया था। यमन में पनपे गृहयुद्ध के पीछे भी इन दोनों देशों की शत्रुता का हाथ था। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने कहा है कि इन समझौतों से इस्लामिक एकता के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इससे विश्व में तनाव कम होगा। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। फिलिस्तीन के इस्लामिक आतंकी संगठन हमास ने कहा है कि इस समझौते से फिलिस्तीन की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी।

इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए समझौते को इजरायल के लिए खतरा बताया है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री यैर लापिड ने कहा है कि यह समझौता इजरायल की विदेश नीति की विफलता का सबूत है। इससे अमेरिका के हितों को भारी धक्का लगा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच शुरू से ही तटस्थ भूमिका निभाई थी। इसलिए उसे अपने प्रयासों में सफलता मिली है। विश्व राजनीति के जानकारों की राय है कि ईरान के खिलाफ अरब देशों के साथ गठबंधन करने का इजरायल और अमेरिका ने जो सपना देखा था, वह इस घटना से चकनाचूर हो गया है। इस समझौते से मध्य-पूर्व में ईरान की स्थिति मजबूत होगी और अब मिस्र आदि अनेक अरब देशों को ईरान के साथ समझौता करना पड़ेगा। इससे यमन में गृहयुद्ध समाप्त होगा और लेबनान में संकट के समाधान में भी सहायता मिलेगी। जबकि अमेरिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है, जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन होगा।

इत्तेमाद (12 मार्च) ने इसे मुस्लिम जगत के लिए रमजान का तोहफा करार दिया है।

इत्तेमाद (15 मार्च) के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि इस समझौते से मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के साथ भी ईरान के नए दोस्ताना संबधों की शुरुआत होगी। अब बहरीन ने भी ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को पुनः शुरू करने का संकेत दिया है। गौरतलब है कि बहरीन काफी समय से ईरान के खिलाफ अभियान चला रहा था और उसके विदेश मंत्रालय की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा था कि ईरान बहरीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके बहरीन की जनता को शासकों के खिलाफ भड़का रहा है। वहीं 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के साथ मिस्र के संबंध बहुत कटु हो गए थे। **सालार** (13 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब और ईरान के बीच बीजिंग में जब समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो उस समय चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। इस समझौते के बाद अब सऊदी अरब की सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है और इससे बशर अल-असद की सरकार मजबूत होगी।

सियासत (12 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस समझौते का स्वागत किया है और कहा है कि इससे अमेरिका को गहरा धक्का लगा है और विश्व की राजनीति में चीन की भूमिका बढ़ी है। इस समझौते से यमन और सीरिया में युद्ध समाप्त होने की आशा बढ़ गई है। इस्लामिक जगत की एकता में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

कौमी तंजीम (12 मार्च) ने अपने संपादकीय में इस समझौते का स्वागत किया है और यह आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही चीन में सऊदी अरब के शाह और ईरान के राष्ट्रपति के बीच उच्चस्तरीय बैठक हो सकती है। समाचारपत्र ने इसे चीन की डिप्लोमेटिक जीत बताई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इसका स्वागत करते हुए कहा है कि इससे इस्लामिक जगत की एकता बढ़ेगी।

रोजनामा सहारा (12 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह दावा किया था कि अमेरिका की सहायता के बिना सऊदी सरकार दो सप्ताह भी नहीं टिक सकती। चीन के प्रयास से हुआ यह समझौता अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा है। चीन ने वह काम कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी देश ने नहीं की होगी। इस फैसले से विश्व की राजनीति में चीन का वर्चस्व बढ़ा है।

इंकलाब (13 मार्च) के अनुसार बहरीन ने भी ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बहाल करने का संकेत दिया है। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि इस समझौते के बाद ईरानी रियाल के मूल्य में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

टिप्पणी : ईरान और सऊदी अरब के बीच शुरू से ही संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इसका कारण यह है कि सऊदी अरब के शासक कट्टर सुन्नी और वहाबी हैं, जबकि ईरान प्रारंभ से ही शिया देश रहा है। शियाओं और सुन्नियों के संबंध शुरू से ही शत्रुतापूर्ण रहे हैं। यहां तक कि इन दोनों के बीच कलमे में भी फर्क है। सुन्नी हजरत अली को इस्लाम का चौथा खलीफा मानते हैं। जबकि शिया उन्हें इस्लाम के पहले खलीफा का दर्जा देते हैं। वे तीन खलीफाओं अबु बक्र, उस्मान और

उमर को खलीफा स्वीकार नहीं करते। उनका दावा है कि पैगम्बर मोहम्मद ने अपने दामाद हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मगर पैगम्बर के ससूर अबु बकर ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए स्वयं को इस्लाम का पहला खलीफा घोषित कर दिया। शियाओं और सुन्नियों का आपसी इतिहास भी काफी रक्तरंजित रहा है। शियाओं का दावा है कि उनके नौ इमामों की निर्मम हत्या सुन्नियों के खलीफाओं के आदेश से की गई। हालांकि, इस्लाम के ये दोनों प्रमुख संप्रदाय कुरान को मानते हैं। मगर दोनों के भाष्य में भारी अंतर है। भारत में भी मुसलमानों के शासनकाल में सुन्नी और शिया शासकों के बीच खूनी संघर्ष का एक लंबा इतिहास है।

प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की का खलीफा जर्मनी का सहयोगी था। इस युद्ध में हार के बाद ब्रिटेन ने कूटनीति से काम लेकर तुर्की के नेता कमाल अतातुर्क की सहायता से खिलाफत को हमेशा के लिए समाप्त करवा दिया। अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय को तुर्की से भागकर फ्रांस में शरण लेनी पड़ी। ब्रिटेन ने खलीफा के साम्राज्य को एक दर्जन से भी अधिक देशों में विभाजित करके वहां पर अपनी कठपुतलियों को शासक के रूप में स्थापित किया। भारत में भी मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाकर खिलाफत की बहाली की मांग की थी और उनका साथ महात्मा गांधी और कांग्रेस ने दिया था।

नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन

मुंबई उर्दू न्यूज (13 मार्च) के अनुसार इजरायल में न्याय व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया है, उसके खिलाफ इजरायली जनता दस सप्ताह से प्रदर्शन कर रही है। 11 मार्च को इजरायल के इतिहास में पहली बार इजरायल के विभिन्न नगरों में पांच लाख से अधिक लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इजरायल के शहर तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों की संख्या दो लाख से भी अधिक बताई जाती है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि न्यायतंत्र में किया गया यह परिवर्तन लोकतंत्र के खिलाफ है। जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि इससे न्याय व्यवस्था में सुधार होगा।

इजरायली अखबारों ने इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन करार दिया है। इजरायल में विपक्ष के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री यैर लापिड ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि इजरायल इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। इस्लामिक आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। ईरान ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता करके हमारे सारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया है। अमेरिका के प्रयास से इजरायल ने छह अरब देशों से जो अब्राहम समझौता किया था, वह मिट्टी में मिल

गया है। मगर इजरायल सरकार को इस संकट की कोई परवाह नहीं।

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार इजरायली संसद ने नेतन्याहू की सरकार को मजबूत बनाने के लिए कानूनी मंजूरी दे दी है। संसद में पारित एक कानून के अनुसार नेतन्याहू को अब अपदस्थ नहीं किया जा सकता। संसद में इस संदर्भ में पेश विधेयक के पक्ष में 61 और विरोध में 51 मत प्राप्त हुए। इस विधेयक के अनुसार संसद के 90 सांसदों का बहुमत ही किसी प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर सकता है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस विधेयक को जिस तरह से संसद मे समर्थन मिला है, उससे नेतन्याहू की स्थिति मजबूत हो गई है।

ईरान में प्रदर्शनकारियों को आम माफी की घोषणा

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार ईरान सरकार ने हाल ही में देश में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 22 हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को आम माफी देने की घोषणा की है। जबकि ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी ने यह दावा किया है कि अब तक सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने वाले 42 हजार लोगों को माफ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रदर्शनकारियों को हिजाब विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक कुर्द युवती महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अब देश की शांति व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्हें आम माफी देने की घोषणा की गई है।

तुर्की को सऊदी अरब की सहायता

सियासत (8 मार्च) के अनुसार आर्थिक संकट का शिकार तुर्की को इस संकट से उबारने के लिए अब सऊदी अरब मैदान में आ गया है। इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत सऊदी अरब तुर्की के केंद्रीय बैंक में पांच बिलियन डॉलर जमा करवाएगा। इस समझौते पर सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट (एसएफडी) के अध्यक्ष अहमद अकील अल-खतीब और तुर्की के केंद्रीय बैंक के गवर्नर साहप कविसिओगलु ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर हुआ है।

मीडिया के अनुसार इस समझौते से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को अपने देश में व्याप्त आर्थिक संकट से निपटने में सहायता मिलेगी और इससे आगामी चुनाव में उनके फिर से जीतने की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष के आर्थिक

संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तुर्की की करेंसी 'लीरा' के मूल्यों में भारी कमी हुई थी। इस समझौते से यह भी संकेत मिलता है कि इन दोनों देशों के बीच इस्लामिक जगत में वर्चस्व को लेकर जो शीत युद्ध चल रहा था, उसका अब खात्मा हो गया है। यह समझौता एर्दोगान की भारी राजनीतिक सफलता का परिचायक है।

तुर्की के वित्त मंत्री नुरुद्दीन नबाती ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से तुर्की आर्थिक संकट को समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही तुर्की का विदेशी मुद्रा भंडार 130 अरब डॉलर का हो जाएगा। पाकिस्तान को भी आर्थिक संकट से उबारने के लिए सऊदी अरब ने भारी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सऊदी अरब पाकिस्तान में 100 मिलियन डॉलर का पूंजी निवेश करेगा। इससे पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और वहां पर तेजी से जो मूल्य वृद्धि हुई है उस पर नियंत्रण में सहायता मिलेगी।

सऊदी अरब, कतर और मिस्र अस्त्र–शस्त्रों के दस बड़े खरीदारों में शामिल

कौमी तंजीम (14 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब, कतर और मिस्र पिछले पांच वर्षों में विश्व के अस्त्र-शस्त्र खरीदने वालों में सर्वोच्च देशों में शामिल हो गए हैं। यह खुलासा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने 2018 से 2022 के बीच विदेशों से खरीदे गए सौदों में 9.6 प्रतिशत हथियार खरीदे हैं। इनमें विमान, एयर रक्षा कवच, बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल, जलपोत आदि शामिल हैं। ये अस्त्र-शस्त्र अमेरिका, फ्रांस और स्पेन से खरीदे गए हैं। अमेरिका से सऊदी अरब ने 91 आधुनिक युद्ध विमान और 20 हजार से ज्यादा आधुनिक मिसाइल और गाइडेड बम खरीदे हैं।

पिछले पांच वर्षों में कतर हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा खरीददार है। कतर ने भी युद्ध विमान, रक्षा कवच, मिसाइल, जलपोत, पनडुब्बियां आदि खरीदे हैं। इनमें से 42 प्रतिशत अमेरिका से, 29 प्रतिशत फ्रांस से और 14 प्रतिशत इटली से खरीदे गए हैं। फ्रांस से उसने 36 राफेल और अमेरिका से 36 एफ 16 लडाकू विमान खरीदे हैं। मिस्र विश्व बाजार में अस्त्र-शस्त्र खरीदने वाला छठा बड़ा देश है। इससे पूर्व यह तीसरे नंबर पर था। किंतु अब उसकी खरीददारी में 5.5 प्रतिशत की कटौती हुई है। 2018 से 2022 के बीच मिस्र ने रूस से जो अस्त्र-शस्त्र खरीदे, उसमें पिछले दशक की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब मिस्र रूसी अस्त्र-शस्त्र खरीदने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। उसकी खरीददारी में रूस का 34 प्रतिशत, इटली का 19 प्रतिशत और फ्रांस का 19 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कुवैत, अल्जीरिया, मोरक्को, जॉर्डन, बहरीन और इराक ने भी सबसे ज्यादा अस्त्र-शस्त्र अमेरिका से खरीदे हैं, जो उनकी खरीददारी का 54 प्रतिशत हिस्सा है। रूस से 8.5 प्रतिशत और इटली से 8 प्रतिशत अस्त्र-शस्त्र इन देशों ने खरीदे हैं।

मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में न्यूज चैनल पर जुर्माना

सालार (2 मार्च) के अनुसार न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने 'न्यूज18 इंडिया' पर मुसलमानों के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने के आरोप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एनबीडीएसए के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. सिकरी ने यह भी निर्देश दिया है कि न्यूज18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा के बयानों की भी जांच की जाए, जिसमें मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है और उन्हें बदनाम किया गया है।

गौरतलब है कि 6 अक्टूबर 2022 को इंद्रजीत घोड़पडे ने अधिकरण के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि इस चैनल ने अपने एक शो में मुसलमानों को बदनाम किया है और उनकी नकारात्मक छवि पेश की है। अधिकरण के जवाब में न्यूज18 ने कहा था कि यह कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया है और यह शो गुजरात के खेड़ा जिला में गरबा के मौके पर हुए पथराव और शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से संबंधित था।

सऊदी अरब के विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा

मुंबई उर्दू न्यूज (5 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने अपने देश के विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। सऊदी योग कमेटी की अध्यक्ष नौफ मारवाई ने घोषणा की है कि सऊदी अरब की विभिन्न विश्वविद्यालयों में योग की शिक्षा देने के लिए समझौते किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग विद्या शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है।

गौरतलब है कि सऊदी सरकार ने 16 मई 2021 को देश में योग विद्या को प्रोत्साहन देने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसका प्रमुख भारत में योग विद्या में प्रशिक्षित एक महिला को नियुक्त किया गया था। नौफ मारवाई को 2018 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। गत वर्ष सऊदी अरब में पहला योग समारोह का आयोजन किया गया था, जोकि चार दिनों तक जारी रहा और इसमें एक हजार लोगों ने हिस्सा लिया था।

सन्यासी के देवबंद में प्रवेश पर रोक

मुंबई उर्दू न्यूज (1 मार्च) के अनुसार जमीयत उलेमा के नेता अरशद मदनी ने दिल्ली में आयोजित जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में हजरत आदम और मनु के एक ही व्यक्ति होने का जो दावा किया था, उसे चुनौती देने के लिए स्वामी यशवीर महाराज देवबंद पहुंच गए। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने चारों वेद ले जा रहे इस स्वामी को रूड़की रोड़ पर ही रोक लिया और उन्हें देवबंद जाने की अनुमति नहीं दी गई।

इस पर पुलिस और स्वामी के समर्थकों में काफी बहस हुई। इसके बाद स्वामी और उनके समर्थकों ने सड़क पर ही धरना दे दिया और हनुमान चालीस पढ़ने लगे। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए इस क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की गई थी। यशवीर महाराज का संबंध मुजफ्फर नगर के योग साधना शिविर से बताया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरशद मदनी ने सनातन धर्म का अपमान किया है। इस पर उन्होंने मौलाना मदनी को पत्र लिखकर उनसे नौ प्रश्न पूछे थे और इस पर उनका स्पष्टीकरण मांगा था। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने के बाद उन्होंने देवबंद जाकर मदनी से बहस करने की घोषणा की थी।

अलीगढ़ में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया

मुंबई उर्दू न्यूज (8 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलीगढ़ में कुछ मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया, ताकि मस्जिदों पर कोई शरारती तत्व रंग न फेंक सके। पुलिस के अनुसार अलीगढ़ के सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था। मस्जिद हलवाईयान के प्रबंधक

ताकि कोई शरारती तत्व मस्जिद पर रंग फेंककर शांति व्यवस्था को भंग न कर पाए। मस्जिद अब्दुल करीम के इमाम ने बताया कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, मस्जिदों को तिरपालों से ढका जा रहा है। हाजी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर हमने मस्जिद को तिरपाल से ढका था, उन्होंने कहा कि ऐसा हम प्रशासन के निर्देश पर करते हैं, ताकि शांति व्यवस्था न बिगड़े।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष का निधन

इंकलाब (11 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश के किछौछा शरीफ की विख्यात दरगाह सैयद शाह मखदूम अशरफ सेमनानी के सज्जादानशीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष सैयद शाह फखरूद्दीन अशरफ का निधन हो गया। उनकी उम्र 73 वर्ष थी और उनकी गणना इस्लाम के बड़े विद्वानों में की जाती थी। उनके निधन पर विभिन्न मुस्लिम नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। बाद में उन्हें हजारों व्यक्तियों की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।

RNI No. DELHIN/2017/72722

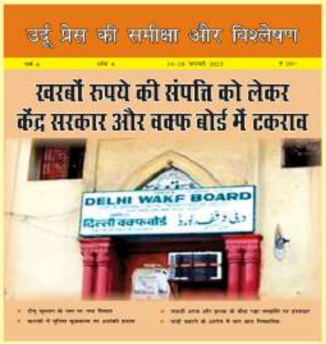

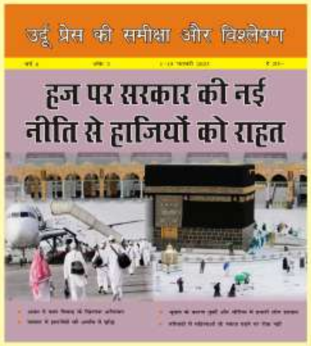

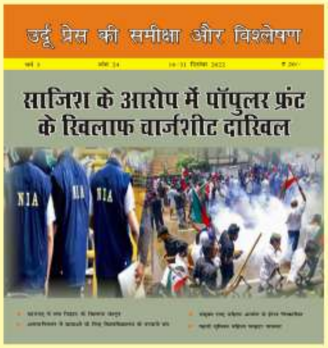

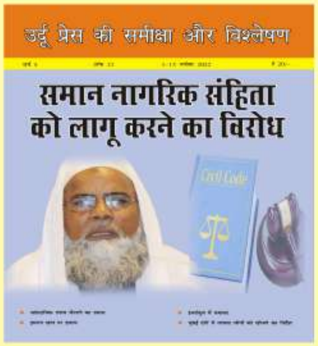

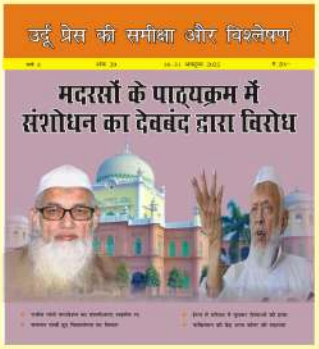

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in